बच्चों से मजदूरी करवाने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाना

†63. **श्री राम नाथ ठाकुरः** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में बाल मजदूरी रोकने के लिए विद्यमान कानून में सजा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण बच्चों से मजदूरी करवाने वाले व्यक्तियों को सजा नहीं मिल पाती है;

(ख) यदि हां, तो बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश करने तथा उनसे मजदूरी करवाने वाले व्यक्तियों को दंड दिए जाने हेतु क्या-क्या प्रावधान हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान बच्चों से मजदूरी करवाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)ः (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया है तथा बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 1.9.2016 से लागू हुआ। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजन या काम पर प्रतिषेध तथा किशोरों (14-18 वर्ष) के अनुसूचित व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन या काम पर प्रतिषेध का प्रावधान है। इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के दण्ड को अधिक कड़ा बनाया गया है तथा नियोजक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किसी बच्चे या किशोर को नियोजित करने का अपराध संज्ञेय बनाया गया है। अधिनियम के उल्लंघन के विरूद्ध दण्ड के मौजूदा प्रावधान इस प्रकार हैंः

(i) अधिनियम का उल्लंघन करके किसी बच्चे या किशोर को नियोजित करने के पहले अपराध के मामले में, दण्ड छह माह तक का कारावास है जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 20,000/- रूपये तक का जुर्माना, जिसे 50,000/- रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों है।

(ii) अधिनियम का उल्लंघन करके किसी बच्चे या किशोर को नियोजित करने के दूसरे या आगामी अपराध के मामले में, न्यूनतम कारावास एक वर्ष होगा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान बाल श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत नियोजकों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार हैः

वर्ष	निरीक्षण	अभियोजन	अपराध-सिद्धियां
2014	268167	3263	1015
2015	236419	1594	595
2016 (आदिनांक तक प्राप्त स्थिति के अनुसार)	173471	384	334

Punishment to people involved in child labour

†*63. SHRI RAM NATH THAKUR: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the people involved in child labour come out clean due to lack of any provision for punishment in the existing law for prevention of child labour in the country;

(b) if so, the provisions providing for punishment against people who are involved in compelling and making children do labour; and

(c) the details of people involved in child labour against whom action has been taken during the last two years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Government has amended the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and enacted the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 which came into force w.e.f. 1.9.2016. The amended Act *inter alia* provides for prohibition on employment or work of children below 14 years of age in any occupation or process and prohibition of employment or work of adolescents (14-18 years) in the scheduled occupations and processes. The punishment for violation of provisions of the Act has been made stricter and the offence of employing any child or adolescent in contravention of the Act by an employer has been made cognizable. The existing penalty provisions against violation of the Act are as under:

(i) In case of first offence of employing any child or adolescent in contravention of the Act, penalty would be imprisonment for a term not less than six months but which may extend to two years or with fine not less than ₹ 20,000/-, but which may extend to ₹ 50,000/- or with both.

(ii) In case of a second or subsequent offence of employing any child or adolescent in contravention of the Act, the minimum imprisonment would be one year which may extend to three years.

(c) As per the information received from the States, the details of action taken against employers under Child Labour Act during the last two years are as under:

† Original notice of the question was received in Hindi.

Year	Inspections	Prosecutions	Convictions
2014	268167	3263	1015
2015	236419	1594	595
2016 (As received till date)	173471	384	334

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति जी, मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 'बाल मजदूरी' शब्द की व्याख्या किन-किन तथ्यों के आलोक में की जाती है तथा उनकी उम्र, उनके परिवेश और उन परिवारों की पृष्ठभूमि क्या है?

श्री बंडारू दत्तात्रेयः सभापति जी, मैंने जो उत्तर दिया है, उसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। वह इसलिए दी है कि इस सरकार के आने के बाद हमने पहली बार एक बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया है, जिसके अन्तर्गत बाल श्रम से बहुत सी जगह अलग-अलग एस्टाब्लिशमेंट्स में काम कराना, सारी एनजीओज़ और इन सारे मामलों को देखते हुए हम जो प्रोविजन लाए हैं, जो अमेंडमेंट्स किए हैं, वह इसमें एक बहुत बड़ा और आमूल परिवर्तन है। इसमें पहली बार 1 सितम्बर, 2016 से हमने 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को किसी भी कारखाने में एम्प्लॉय करने को पूरी तरह से निषेध किया है। इस एक्ट में 14 से 18 साल के जो किशोर हैं, उनके लिए एक नयी definition देकर उन्हें adolescent कह कर हमने एक्ट में परिवर्तन किया है, अमेंडमेंट किया है। तो वही एक्ट अभी आगे आया है। लेकिन आपका भी जो विषय है, तो हम लोगों ने इस कानून का और सख्ती से पालन करने का प्रोविजन भी किया है। परिवार के बारे में आपने जो कहा, तो परिवार के बारे में भी हम लोगों ने रूल्स फ्रेम करके अपने देश की जो परिस्थिति है, उसको देख कर परिवार में खुद के पिता जी के भाई या बहन के परिवार में काम करने का प्रावधान किया है। बाकी यह है कि इसमें भी employee-employer का relation नहीं है। वह भी सीमित है। वह केवल 2 घंटे उनकी सहायता कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। यानी इसमें किधर भी employee-employer का relation नहीं है, वह केवल सहायता कर सकता है। हमने इसमें काफी सोच कर किया है कि हमारे देश में बहुत से घरों में छोटे-छोटे काम करने वाले हैं और वे काम भी सीखते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, उनको school hours में total prohibition है। हमने Right to Education Act को भी इसमें मिलाया है। तो हमने इसमें परिवार के बारे में बहुत कुछ रूल्स में फ्रेम किया है। अगर एक बार उन रूल्स को थोड़ा समझेंगे, तो उसका समाधान मिलेगा।

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति महोदय, बाल मजदूरी को चिन्हित कर उनकी पुनर्स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

SHRI BANDARU DATTATREYA: I could not follow the question. ...(*Interruptions*)...

श्री राम नाथ ठाकुरः मैं बाल मजदूरी को चिन्हित कर उनकी पुनर्स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा जानना चाहता हूँ।

SHRI BANDARU DATTATREYA: I was unable to really follow the question first because...

श्री हरिवंशः आपने तीन वर्षों में कितने बाल मजदूरों को identify किया और कितनों को rehabilitate किया, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्यः तीन सालों में कितने बाल मजदूर identified हुए और क्या कार्रवाई की गई? ...(**व्यवधान**)...

श्री बंडारू दत्तात्रेयः उसका आंसर मैंने दिया है। इसमें मैंने State-wise information भी दी है। अभी number of working children in 2001 census ...(**व्यवधान**)...

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः एक मिनट। आप जवाब सुन लीजिए।

श्री बंडारू दत्तात्रेयः मैंने एक्ट में जो प्रावधान किये थे, उसमें rehabilitation fund का भी किया गया था। अभी तीन साल के अन्दर का जो data हमारे पास है, उसके अनुसार 2013-14 में 64,050, 2014-15 में 1,16,000 और 2015-16 में 59,076 किया गया, because rehabilitation is one of the major points. For rehabilitation, a separate fund has been provided. In rehabilitation, Sir, for the first time the employers' contribution and, after rescuing the children, the State Government should contribute ₹ 15,000 towards rehabilitation fund. So, ultimately, all these funds, employers' contribution and also State Government's contribution, will go into the bank account of the rescued children. And with regard to enforcement also, I have already given. So far as enforcement is concerned, हमने जवाब में 2014-15 और 2015-16 में हुए inspections के बारे में दिया है। हमें दो चीजों से दिक्कत होती है। पहला तो यह है कि स्टेट गवनर्मेंट से information मिलने में हमें बहुत दिक्कत होती है। मैंने तो आपको बिहार का समाचार बताऊंगा। बिहार ही नहीं, बल्कि बहुत से राज्यों की यही हालत है। हमारे पास केवल 13 राज्यों का information आया है, बाकी राज्यों की information नहीं है। The subject matter of 'labour' falls under the Concurrent List. Hence, it should be enforced by the appropriate Government.

DR. NARENDRA JADHAV: Sir, in every eleven children, one child is engaged in child labour. According to the Census 2011, there were about 1,13,00,000 child labour. Then, 62.8 per cent of the adolescents, aged between 15 and 17, are engaged in hazardous works. Against this background, the numbers provided by the hon. Minister clearly show that the inspection rate is abysmally low. The conviction rate is also very poor. And, it is further falling. The question again is, why? Does that not mean ineffective implementation of the new Act, which has been passed?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, as I mentioned, the enforcement is very stringent under the new Act. We have, now, made it a cognizable offence. If I compare the old Act and the new Act, earlier the minimum penalty was ₹ 10,000,

which could extend up to ₹ 20,000. Now, the maximum penalty has been increased up to ₹ 50,000. We have also increased the imprisonment in case of a repeated offence. Earlier, for the first time offence, the imprisonment term was three months. Now, we have enhanced it to six months. Earlier the maximum imprisonment was one year. Now, the maximum imprisonment has been increased to two years. That is we have doubled the punishment. Secondly, the employment of adolescents, aged between 14 to 18, is totally banned in hazardous activities. We have also provided a new list of scheduled employment activities. So, the definition of 'hazardous activities' has been changed. The definition of 'adolescents' has also been provided. Thus, the engagement of adolescents in hazardous activities is totally banned.

श्री अमर शंकर साबलेः सभापति महोदय, अभी जिन बच्चों की बात चल रही है, वह तो चलते-फिरते बच्चों की बात चल रही है। महोदय, जो दूध-पीता बच्चा होता है, वह हंसता है, रोता है, लेकिन रास्ते पर भीख मांगने वाली जो औरतें होती हैं, उनके पास जो बच्चा होता है, वह कभी रोता नहीं है, क्योंकि उसको नशे की दवा दी जाती है ताकि लोगों के मन में दया उत्पन्न हो। उस नशे की दवा का उस बच्चे के शरीर और मस्तिष्क पर परिणाम होता है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में केंद्र सरकार की क्या सोच है?

श्री बंडारू दत्तात्रेयः सर, हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट है, लेकिन the Women and Child Welfare Department is a separate one. But, we have a provision according to which if such children are there in rehabilitation centres, then, with the help of the National Rural Health Mission, we are handling their problem.

SHRI K. K. RAGESH: Mr. Chairman, Sir, many reports reveal the fact that the children who are engaged in child labour are, basically, from socially and educationally backward sections. Even after 15 years of our Constitutional Amendment that made the Right to Education as a fundamental right, around 80 lakh children are still out of school. Majority of those children who are out of school are from socially and educationally backward sections. Sir, my question is, rather than imposing certain penal provisions to curb child labour, whether the Government is aware of or taking care of the aspect of social and educational backwardness also so as to curb the child labour. That is my question, Sir. Thank you.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I agree with the hon. Member that the main reason for child labour is poverty and illiteracy. Because of poverty and illiteracy, as the hon. Member has already mentioned, the number of children who are out of school is also increasing. What I am saying is that in the new Amendment Act, we have proposed to give powers to the District Magistrate and the District Magistrate, in turn, can delegate his powers to subordinates. For them also, we have made a provision in the rules that if a teacher, or, the school management has any

[Shri Bandaru Dattatreya]
information about such children who were earlier coming to schools but now they are unable to come, even they can, with the help of the District Magistrate, go ahead with the process which has been put forth.

*64. **[The Questioner was absent.]**

Slow growth of manufacturing sector

*64. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the country's manufacturing sector has been in trouble for last three years;

(b) whether it has become a challenge for the country's private as well as State-owned firms; and

(c) the details of steps taken by Government to safeguard the interests of the country's private and public sector firms and to enable them to sell product sin global markets at competitive prices?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the Index of Industrial Production (base year 2004-05), growth in manufacturing sector was (-) 0.8% in 2013-14 and thereafter registered a growth of 2.3% and 2.0% in the years 2014-15 and 2015-16 respectively. During the period April-November, 2016, the manufacturing sector registered a growth of (-) 0.3% over the corresponding period last year.

(b) and (c) The Government has been taking various initiatives to promote manufacturing and exports. These *inter alia*, include Make in India, Startup India, reforms in Foreign Direct Investment (FDI) policy, facilitating building of infrastructure, Skill India, and improving business environment. These initiatives contribute to improving competitiveness of private and public sector firms operating in the country, facilitating their integration into the Global Value Chains and enabling them to better compete in global markets. Some of these measures are listed below:

(i) A number of measures have been undertaken to ease business environment. Industrial licensing has been simplified and liberalized with a large number of components of Defence Products' list excluded from its purview. Various